



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2003/आषाढ़ 31, 1925

No. 332]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2003/ASADHA 31, 1925

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा निबंधन विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 9 जून, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 557 (अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खंड (i) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 21/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

1. नाम और प्रारंभ :

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।

(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा :

“ 5अ. विदेशी दूतावास/राजदूत/कॉन्सुलेट जनरलों द्वारा अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री

विदेशी दूतावास/राजदूत/कॉन्सुलेट जनरल भारत में कृषि भूमि/वृक्षरोपण संपत्ति/फार्म हाउस के सिवाय अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री कर सकता है बशर्ते कि (i) ऐसी खरीद/बिक्री के लिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त की गई हो और (ii) भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण बैंकिंग माध्यम से विदेश से प्राप्त निधियों से किया गया हो ”।

[सं. फे. मा. 93/2003-आर बी]

कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(Exchange Control Department)
(Central Office)
NOTIFICATION

Mumbai, the 9th June, 2003

Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 557 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub-section (3) of Section 6, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 21/2000-RB dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations 2000, namely :—

1. Short title and Commencement:—

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations :

In the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations 2000, after Regulation 5, the following Regulation shall be inserted namely :

“5A. Purchase/Sale of Immovable Property by Foreign Embassies/Diplomats/Consulate Generals

A Foreign Embassy/Diplomat/Consulate General may purchase/sell immovable property in India other than agricultural land/plantation property/farm house provided (i) clearance from Government of India, Ministry of External Affairs is obtained for such purchase/sale, and (ii) the consideration for acquisition of immovable property in India is paid out of funds remitted from abroad through banking channel”.

[No. FEMA. 93/2003-RB]

K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 18 जून, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 558 (अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) दूसरा संशोधन विनियमावली, 2003 कहलाएगा।

(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000,

अ. विनियम 2 में,

(i) मद (vii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, नामतः :—

“(vii) (क) अनिवासी भारतीय (एन आर आई) का विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से संबंधित फर्म अथवा संपत्ति में निवेश) विनियमावली, 2000 के विनियम 2 के खंड (iv) में दिया गया अर्थ लागू होगा।”

(ii) मद (viii) में ‘अनिवासी भारतीय (एन आर आई)’ शब्द निकाल दिया जाए;

आ. विनियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, नामतः :—

“6अ. बोनस शेयर का अभिग्रहण :—

भारतीय कंपनी अनिवासी शेयरधारकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन बोनस शेयर जारी कर सकते हैं :

- (क) ऐसे शेयर (इसके पश्चात् “मूल शेयर” माना जाएगा), जिनके तहत कंपनी द्वारा बोनस शेयर जारी किए गए हैं, वे अभिग्रहण को लागू नियमों/विनियमों के अनुसार अनिवासी शेयरधारक द्वारा अभिगृहीत अथवा धारित किए गए थे।
- (ख) अनिवासी शेयरधारक द्वारा अभिगृहीत बोनस शेयर, मूल शेयरों को लागू प्रत्यावर्तनीयता से संबंधित प्रतिबंधों समेत उन्हीं शर्तों के अधीन होंगे।

“6आ. भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट :—

विनियम 6, या विनियम 6अ, जैसा भी मामला हो, के अनुसार अधिकार शेयर अथवा बोनस शेयर जारी करने वाली कंपनी लेनदेन को निर्गम की तिथि से तीस दिनों के भीतर फॉर्म एफसी-जीपीआर में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को रिपोर्ट करें।

इ. विनियम 9 में उप-विनियम (2) निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—

“(2) (i) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति, अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी निकाय न होने पर, उनके द्वारा धारित शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति को बिक्री अथवा उपहार द्वारा अंतरित कर सकते हैं।

(ii) अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी निकाय उनके द्वारा धारित शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को अन्य अनिवासी भारतीय या विदेशी कंपनी निकाय को ही बिक्री या उपहार द्वारा अंतरित कर सकते हैं ;

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें शेयर अंतरित किए जा रहे हों, ने खंड (i) और (ii) के अनुसार केन्द्र सरकार से शेयर को अभिगृहीत करने की पूर्वानुमति प्राप्त की हो, यदि उनका शेयर अथवा डिबेंचरों में निवेश अथवा तकनीकी सहभागिता अथवा ट्रेड मार्क करार अथवा उसी क्षेत्र में किसी भी नाम से जाने जाने वाले निवेश अथवा संबद्ध क्षेत्र में रत जिसमें भारतीय कंपनी जिनके शेयर अंतरित किए जाने वाले हैं के जरिए उनके पूर्व उद्यम अथवा भारत में तालमेल है।

इसके अलावा, बशर्ते कि खंड (i) और (ii) की प्रतिबंध, एशियन विकास बैंक (एडीबी), अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आई एफ सी), कॉमनवेल्थ विकास निगम (सीडीसी) इयूरोप एंटविकलिंग्स गेस्सेल्सशिप्ट (डीईजी) ऐसे अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं को और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रत भारतीय कंपनी के शेयर अंतरण पर लागू नहीं हैं।

(iii) इन विनियमों के अनुसार भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति उनके द्वारा धारित भारतीय कंपनी के शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचरों को—

(क) भारत में निवासी व्यक्ति को उपहार के रूप में अंतरित कर सकता है

(ख) पंजीकृत दलाल के जरिए भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकता है।”

ई. सूची 1 में

(क) पैरा 5 में खंड (क) “सेबी के दिशा-निर्देशों” शब्दों के पश्चात् “यथा लागू” शब्दों को जोड़ा जाएगा;

(ख) पैरा 5 के पश्चात् निम्नलिखित नया पैरा समाविष्ट किया जाए नामतः :—

“5अ. ए डी आर/जीडीआर का निर्गम मूल्य

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को जारी किए जाने वाले एडीआर/जीडीआर का मूल्य भारतीय कंपनी द्वारा निश्चित किया जाए।

(क) जहां निर्गम के अग्रणी प्रबंधक के साथ परामर्श करके सार्वजनिक आधार पर निर्गम जारी किया जाता है; और

(ख) अन्य मामलों में, उक्त पैरा 5 में दिए गए अनुसार”

(ग) पैरा 6 में खंड (क) में उप-खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा नामतः :—

“(iii) 14 जुलाई, 2000 (अर्थात् वह तारीख जिस दिन लाभांश संतुलन शर्त को निकाला गया) के पश्चात् घोषित/प्रेषित भागों में निर्मित दायित्व को”

(घ) पैरा 6 में वर्तमान उप-खंड (ख) निकाल दिया जाए।

ठ परिशिष्ट अ के स्थान पर संशोधित परिशिष्ट “अ” प्रतिस्थापित की जाए

ऊ परिशिष्ट आ के स्थान पर संशोधित परिशिष्ट “आ” प्रतिस्थापित की जाए

ए परिशिष्ट इ के स्थान पर संशोधित परिशिष्ट “इ” प्रतिस्थापित की जाए

ऐ परिशिष्ट ई के स्थान पर संशोधित परिशिष्ट “ई” प्रतिस्थापित की जाए

औ वर्तमान फॉर्म एफसी-जीपीआर के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित एफसी-जीपीआर फॉर्म प्रतिस्थापित किया जाए,

औ अनुसूची 2, में पैरा (1) में उप-पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए नामतः :—

" (5) (अ) पंजीकृत एफआईआई को प्रस्ताव/प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये भारतीय कंपनी के शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने की अनुमति है बशर्ते कि इस पैरा के उप-पैरा (4) में उल्लिखित सीमा के अधीन हो और भारतीय कंपनी को ऐसे शेयर जारी करने की अनुमति हो;

बशर्ते कि :-

- (i) सार्वजनिक प्रस्ताव के मामले में जारी करने वाले शेयर का मूल्य निवासियों को जारी किए गए शेयरों के मूल्य से कम न हों, और
- (ii) प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा निर्गम के मामले में सेबी द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार निकाले गए मूल्य से या पूर्ववर्ती पूंजी निर्गम के नियंत्रण पर प्राप्त जारी दिशा-निदेश, जो लागू हों, से कम न हों"

अ अनुसूची 3 में,

(i) पैरा (1) के उप-पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(i) अनिवासी भारतीय, प्राधिकृत व्यापारी द्वारा नामित शाखा के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथावत् अनुमोदन करके संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकते हैं।"

(ii) पैराग्राफ 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः :-

"3. शेयर और/अथवा डिबेंचर की बिक्री/परिपक्वता आय का प्रेषण/जमा

अनिवासी भारतीय या विदेशी कंपनी निकाय द्वारा इस योजना के अंतर्गत खरीदे गए भारतीय कंपनी के शेयर और/अथवा डिबेंचर की निवल बिक्री/परिपक्वता आय को (आयकर के भुगतान के पश्चात्) पैरा 1 में संदर्भित प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा द्वारा अनुमति दी जाए।

- (क) अनिवासी भारतीय/समुद्रपारीय निगमित निकाय निवेशक के एनआरओ खाते में जमा किया जाए जहां शेयर की खरीद और/या डिबेंचर की बिक्री या भुगतान एनआरओ खाते में जमा निधियों से किया जाता है या जहां शेयर और/या डिबेंचर की खरीद अप्रत्यावर्तनीय आधार पर की जाती है; अथवा
- (ख) जहां शेयर और/अथवा डिबेंचर प्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीदे गए हैं वहां अनिवासी भारतीय/विदेशी निगमित निकाय के निदेशक के विकल्प के अनुसार विदेश में प्रेषित किया जाए अथवा अनिवासी भारतीयों के एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ खाते में जमा किया जाए"

अ: अनुसूची 4 में, पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए नामतः :-

"बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति ने जिन्हें शेयर अंतरित किए जा रहे हों, केन्द्र सरकार से शेयर को अभिगृहीत करने की पूर्वानुमति प्राप्त की हो, यदि उनका, शेयर अथवा डिबेंचरों में निवेश अथवा तकनीकी सहभागिता अथवा ट्रेड मार्क करार अथवा उसी क्षेत्र में किसी भी नाम से जाने जाने वाले निवेश अथवा संबद्ध क्षेत्र में रत जिसमें भारतीय कंपनी जिनके शेयर अंतरित किए जाने वाले हैं के जरिए उनके पूर्व उद्यम अथवा भारत में तालमेल है।"

इसके अलावा यह भी कि ये प्रतिबंध, एशियन विकास बैंक (एडीबी) अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) कॉस्मोवैल्थ विकास निगम (सीडीसी, ड्यूश) एंटविकलिंग्स गेस्सेल्सशॉफ्ट (डीईजी) जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं को और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रत भारतीय कंपनी के शेयर अंतरण पर लागू नहीं हैं।

[सं० फेमा. 94/2003-आर बी]

उपा थोरात, कार्यपालक निदेशक

परिशिष्ट "अ"

(पैराग्राफ 2 देखें)

(अ) ऐसे कार्यकलापों की सूची जिनके लिए भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का स्वचालित मार्ग (ऑटोमेटिक रूट) उपलब्ध नहीं है

1. घरेलू एयरलाइन
2. पेट्रोलियम क्षेत्र (निजी क्षेत्र तेल शोधन के सिवाय)
3. मूलभूत ढाँचा और सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियां
4. रक्षा और उसके अनुकूल उद्योग
5. परमाणु खनिज
6. प्रिंट मीडिया
7. प्रसारण
8. डाक सेवाएं
9. कूरियर सेवाएं
10. सेटेलाइट की स्थापना और परिचालन
11. एकीकृत टाउनशिप का विकास
12. चाय क्षेत्र

(आ) ऐसे कार्यकलापों की सूची जिनके लिए एफडीआई प्रतिबंधित है

1. खुदरा व्यापार
2. परमाणु ऊर्जा
3. लॉटरी कारोबार
4. जुआ और सट्टेबाजी
5. आवास और अचल संपत्ति कारोबार
6. कृषि (पुष्पखेती, बागबानी, बीजों की उपज, पशुपालन, मछली पालन, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रित शर्तों और सेवाओं के अधीन सब्जी, मशरूम आदि की खेती को छोड़कर) और बागान. (चाय बागान का छोड़कर)।

परिशिष्ट "आ"

(पैराग्राफ 2 देखें)

भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा निवेशों पर सेक्टरल कैप

सेक्टर	निवेश कैप	कार्यकलाप/मद/स्थिति का वर्णन
1	2	3
1. निजी क्षेत्र बैंकिंग	49 %	रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गये दिशा-निर्देशों के अधीन
2. गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	100 %	नीचे दर्शाये गये स्तर के अनुसार एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी में निवेश निम्नलिखित 19 एनबीएफसी गतिविधियों में अनुमत है।

(क) शामिल कार्यकलाप :

1. मर्चेंट बैंकिंग
2. अंडरराइटिंग
3. संविभाग प्रबंध सेवा
4. निवेश परामर्श सेवा
5. वित्तीय परामर्श
6. स्टॉक- ब्रोकिंग
7. आस्ति प्रबंध
8. उद्यम पूंजी
9. कस्टोडियल सेवा
10. फैक्टरिंग
11. क्रेडिट रेफरेंस एजेंसियां
12. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां
13. लीजिंग तथा वित्त
14. आवासीय वित्त
15. फॉरेक्स ब्रोकिंग
16. क्रेडिट कार्ड कारोबार
17. मुद्रा विनिमय कारोबार
18. माइक्रो ऋण
19. ग्रामीण ऋण

(ख) एनबीएफसी के आधार पर निधि के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड :

- (i) 51 प्रतिशत तक एफडीआई के लिए हो तो 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट के रूप में लाया जाए।
- (ii) अगर एफडीआई 51 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत तक हो तो 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट के रूप में लाया जाए।
- (iii) अगर एफडीआई 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक हो तो 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, जिसमें 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट के रूप में और शेष 24 महीनों में लाया जाए।

1	2	3
		(ग) गैर-निधि के आधार पर कार्यकलापों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड। 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड विदेशी निवेश के साथ गैर-निधि पर आधारित एनबीएफसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को लागू है।
		(घ) विदेशी निवेशक, भारतीय सत्ता की इक्विटी के कम से कम 25 प्रतिशत के विनिवेश की शर्त के अलावा 100 प्रतिशत तक परिचालनात्मक सहायक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि उक्त (ख)(iii) के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर लाने के अधीन (अतिरिक्त पूंजी लाये बिना परिचालनात्मक सहायक कंपनियों की संख्या के प्रतिबंध को छोड़कर)।
		(ङ.) एनबीएफसी परिचालन के संयुक्त उद्यम जिनके 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश हैं उन्हें भी अन्य एनबीएफसी क्रियाकलाप उपक्रम के लिए कंपनियां स्थापित करने की भी अनुमति होगी बशर्ते कि कंपनियां भी न्यूनतम पूंजी अंतर्वाह अर्थात् (ख)(i) और उक्त (ख)(ii) का अनुपालन करें।
		(च) स्वचालित मार्ग पर एनबीएफसी क्षेत्र में एफडीआई डाल दें बशर्ते कि रिजर्व बैंक के दिशा-निदेशों का अनुपालन किया हो। रिजर्व बैंक इस संबंध में उचित दिशा-निदेश जारी करेगा।
3. बीमा	26 %	बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 26% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है बशर्ते कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से लाइसेंस प्राप्त किया हो।
4. दूरसंचार	49 %	(i) सेटलाइट द्वारा बेसिक, सेलूलर मूल्यवर्धित सेवाओं में और ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49 प्रतिशत तक सीमित कंपनी जो निवेश करती है और कंपनी जिसमें निवेश किया जाने वाला है, विदेशी इक्विटी कैप और इक्विटी और अन्य लाइसेंस प्रावधानों के अंतरण और जोड़ने के लिए लाइसेंस शर्तें। (ii) आईएसपी के साथ गेटवे, रेडिओ पेजिंग और एण्ड-टु-एण्ड बैंडविड्थ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 74 प्रतिशत तक अनुमति है और 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। ये सेवाएं लाइसेंसिंग और सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन हैं। (iii) उत्पाद कार्यकलापों के लिए इक्विटी कैप लागू नहीं है। (iv) दूरसंचार क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 100 प्रतिशत तक अनुमत है : (क) गेट के उपलब्ध न कराने वाले आईएसपी (सेटलाइट और सबमरीन केबल दोनों के लिए) (ख) डार्क फाइबर उपलब्ध कराने वाले इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (आईपी श्रेणी 1) (ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल और (घ) वॉयस मेल उक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं; (क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 100 प्रतिशत तक अनुमत है यदि यह कंपनियां दुनिया के अन्य क्षेत्रों में सूचीबद्ध हैं बशर्ते कि ऐसी कंपनियां 5 वर्ष में उनके इक्विटी के 26 प्रतिशत तक विनिवेश भारतीय जनता के पक्ष में करें।

1	2	3
		(ख) उक्त सेवाएं लाइसेंसिंग और सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन होंगी, जब आवश्यक हो।
		(v) 49 प्रतिशत से अधिक; विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव पर एफआईपीबी द्वारा मामले दर मामले आधार पर विचार किया जाएगा।
5. पेट्रोलियम रिफाइनिंग (निधि क्षेत्र)	100%	निजी भारतीय कंपनियों के मामले में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।
6. आवास और भूमि भवन		नीचे बताए गए क्षेत्रों में केवल अनिवासी भारतीय/विदेशी कंपनी निकायों को ही 100 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है:
		(क) सुविधायुक्त प्लॉटों का विकास और आवासीय परिसरों का निर्माण
		(ख) भूमि-भवन में निवेश जिसमें व्यापारिक केंद्रों और कार्यालयों सहित आवासीय और घाणिय परिसरों का निर्माण शामिल है।
		(ग) टउनशिप का विकास
		(घ) नगर और क्षेत्रीय स्तर की शहरी मूलभूत सुविधाएं जिसमें सड़कें और पुल शामिल हैं।
		(ङ) भवन सामग्री के विनिर्माण में निवेश जो एनबीएफसी जैसी एफडीआई के लिए भी खुला है।
		(च) ऊपर (क) से (ङ) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सहभागिता उद्यमों में निवेश
		(छ) आवासीय वित्त संस्थाओं में निवेश
7. कोयला और लिग्नाइट		(i) भारतीय निजी कंपनियां जो सीमित उपभोग के लिए पॉवर परियोजनाएं और कोयले अथवा लिग्नाइट की परियोजनाएं लगा रही हैं अथवा उनका कार्य-संचालन कर रही हैं उन्हें 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।
		(ii) कोयला प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है, बशर्ते कि कंपनी कोयला खनन न करे और अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों से खुले बाजार में साफ किया हुआ अथवा टुकड़े किया हुआ कोयला नहीं बेचे। वे ऐसा साफ किया अथवा टुकड़े किया हुआ कोयला उन्हीं पार्टियों को सप्लाई करेंगे जो कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों को साफ करने अथवा टुकड़े करने के लिए कच्चा कोयला सप्लाई करते हैं।
		(iii) सीमित खपत के लिए कोयले अथवा लिग्नाइट का पता लगाने अथवा खनन के लिए 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।
		(ख) (iv) उक्त सभी मामलों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 50 प्रतिशत तक अनुमत है बशर्ते कि ऐसे निवेश पीएसयू के ईक्विटी के 49 प्रतिशत से अधिक न हो।
8. उद्यम पूंजी निधि (बीसीएफ) और उद्यम पूंजी कंपनी (बीसीसी)		समुद्रपारीय उद्यम पूंजी निधियों/कंपनियों की घरेलू उद्यम पूंजी उपक्रम साथ ही साथ अन्य कंपनियों में स्वचालित मार्ग के जरिए निवेश की अनुमति केवल सेबी विनियमावली और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर सेक्टर स्पेसिफिक कैप के अधीन।
9. व्यापार		(i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 51 प्रतिशत तक व्यापार की अनुमति है बशर्ते कि वह प्राथमिक स्वरूप के

1

2

3

क्रियाकलाप और उपक्रम निर्यात गृह/व्यापार गृह/सुपर ट्रेडिंग हाउस/स्टार ट्रेडिंग हाउस हो। तथापि, एफआईपीबी मार्ग के अंतर्गत व्यापारी कंपनियां निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है :

- (क) निर्यात।
- (ख) निर्यात/एक्स बांडेड वेयरहाउस बिक्री के साथ बल्क आयात।
- (ग) कैश एण्ड कैरी खुदरा व्यापार।
- (घ) अन्य वस्तु और सेवाओं का आयात उसी समूह के सरकारी खरीद और बिक्री के लिए कम से कम 75 प्रतिशत तक हो और न कि तीसरे पक्ष के उपयोग अथवा आगे के अंतरण/वितरण और बिक्री के लिए।

(ii) एक्विजिशन नीति के प्रावधानों के अधीन व्यापार के निम्नलिखित मर्दन भी अनुमत हैं :

- (क) बिक्री पश्चात् सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कंपनियां (जो स्वयं एवं व्यापारी नहीं हैं)।
- (ख) संयुक्त उद्यमों के उत्पादों के घरेलू व्यापार थोक स्तर पर अनुमत है ऐसी व्यापारी कंपनियां जिसकी भारत में ईक्विटी सहभागिता है और जो संयुक्त उद्यमों की ओर से निर्मित उत्पादों को बाजार में उतारना चाहते हैं।
- (ग) हाई-टेक वस्तुएं/वस्तुएं जिन्हें बिक्री पश्चात् विशेष सेवाओं की आवश्यकता है।
- (घ) सामाजिक क्षेत्रों के वस्तुओं का व्यापार।
- (ङ) लघु उद्योग क्षेत्र के स्रोत से वस्तुओं का व्यापार जिसके अंतर्गत, तकनीकी आधार और दी गई गुणवत्ता विशेषताओं पर कंपनी उनके ब्रांड नाम से व्यापार कर सकती है।
- (च) निर्यात के लिए उत्पाद का घरेलू स्रोत।
- (छ) ऐसी वस्तुओं की टेस्ट मार्केटिंग जिसके लिए कंपनी को उत्पाद की अनुमति है बशर्ते कि ऐसी टेस्ट मार्केट सुविधा दस साल की अवधि की हो और उत्पादन सुविधाओं में निवेश का प्रारंभ टेस्ट मार्केटिंग के साथ किया हो।
- (ज) ई-कामर्स कार्यकलाप के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है बशर्ते कि अगर ऐसी कंपनियां दुनिया के अन्य भागों से सूचीबद्ध हों, तो पांच साल में वह उनके ईक्विटी के 26 प्रतिशत का निवेश भारतीय जनता के पक्ष में करें। ऐसी कंपनियां केवल कारोबार से ई-कॉमर्स (बी2बी) में रत हो न कि खुदरा व्यापार में।

10. पावर

100%

परमाणु रिएक्टर पावर प्लांट के अलावा बिजली निर्माण, आबंटन तथा वितरण की परियोजना के संबंध में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। परियोजना की लागत तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मात्रा में कोई भी सीमा नहीं है।

1	2	3
11. दवाइयों और औषधियाँ (फार्मास्यूटिकल्स)	100%	<p>दवाइयों और फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, बशर्ते कि कार्यकालावधि को अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता नहीं है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक और विशेष सेल/टिश्यू टारगेटेड फॉर्म्युलेशन्स का उपयोग शामिल है।</p> <p>लाइसेंसीकृत दवाइयों और फार्मास्यूटिकल्स और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से उत्पादित थोक दवाइयाँ और विशेष सेल/टिश्यू टारगेटेड फॉर्म्युलेशन्स में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।</p>
12. रेल और महामार्ग बंदर और बंदरगाह	100%	<p>मार्ग और महामार्ग, वाहन पूल, टोल मार्ग, वाहन टनेल, पक्कन और बंदरगाह के निर्माण तथा रख-रखाव की परियोजनाएं।</p>
13. होटल और पर्यटन	100%	<p>होटलों में ऐसे सभी रेस्तरां, बीच रिजार्ट और अन्य टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं जो पर्यटकों को रहने की जगह और/अथवा खान-पान की सुविधा प्रदान करते हैं। पर्यटन संबंधी उद्योग में ट्रेवल एजेंसियां, टूर ऑपरेटिंग एजेंसियां और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग एजेंसियां, पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक, साहसिक कार्यों और अन्य पशुओं को देखने की सुविधा उपलब्ध कराने वाली यूनिट, पर्यटकों के लिए भू-मार्ग, हवाई-मार्ग और जल-मार्ग से परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले, पर्यटकों के लिए आराम करने, मनो-विनोद, खेल-कूद और स्वास्थ्य संबंधी यूनिट और सम्मेलन/समारोह आयोजित करने वाले यूनिट और संगठन।</p> <p>विदेशी तकनीकी करारों के लिए स्वचालित अनुमति दी जाएगी अगर :</p> <ol style="list-style-type: none"> परियोजना की पूंजी लागत के 3 प्रतिशत तक का प्रस्तावित भूगतान, तकनीकी और परामर्शी सेवा जिसमें आर्किटेक्ट, डिजाइन, पर्यवेक्षण आदि का शुल्क शामिल। निबल पण्यावर्त के 3 प्रतिशत तक फ्रेन्चाइजिंग और मार्केटिंग/प्रचार समर्थन शुल्क, और प्रोत्साहन शुल्क सहित प्रबंध शुल्क के लिए देय सकल परिचालन लाभ का 10 प्रतिशत तक।
14. खनन	74%	<ol style="list-style-type: none"> हीरे और जवाहरात का अन्वेषण और खनन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।
	100%	<ol style="list-style-type: none"> हीरे और जवाहरात को छोड़कर सोने और चांदी और खनिजों का पता लगाना और खनन, धातु कर्म तथा प्रसंस्करण के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।
		<ol style="list-style-type: none"> जहां तक खनन क्षेत्र का संबंध है वहाँ 100 प्रतिशत कंपनियां स्थापित करने के लिए दिनांक 14-12-98 का प्रेस नोट 18 (1998 सिरीज) लागू नहीं होगी बशर्ते कि आवेदक से इस आशय का घोषणापत्र प्राप्त हो कि उनके पास उसी क्षेत्र और/अथवा विशिष्ट खनिज के लिए वर्तमान में संयुक्त उद्यम नहीं है।
15. विज्ञापन	100%	<ol style="list-style-type: none"> विज्ञापन क्षेत्र <p>स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।</p>

1	2	3
16. फिल्में	100%	(ख) फिल्म क्षेत्र (संबंधित सेवाओं/उत्पादों सहित फिल्म का उत्पादन, प्रदर्शन और वितरण) स्वचालित मार्ग पर प्रवेश द्वार बिना शर्त के 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति।
17. हवाई अड्डे	74%	74% से अधिक के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक।
18. अत्यधिक हुत परिवहन प्रणालियाँ	100%	सहयोगी भूमि भवन विकास समेत सभी शहरों में अत्यधिक हुत परिवहन प्रणाली में स्वचालित मार्ग पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 100 प्रतिशत तक अनुमत है।
19. प्रदूषण नियंत्रण और प्रभाव	100%	स्वचालित मार्ग पर प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के एकीकरण के लिए परामर्श, दोनों में।
20. विशेष आर्थिक क्षेत्र	100%	निम्नलिखित के अलावा सभी उत्पादन कार्यकलाप : (i) शस्त्र और एम्बुशिशन, विस्फोटक और सुरक्षा उपस्कर संबंध वस्तु, सुरक्षा हवाई अड्डा तथा युद्ध नौका (ii) परमाणु वस्तु, नॉकॉटिक्स तथा सैकॉटोपिक वस्तु तथा (iii) मादक पेय का डिस्टिलेशन और बूझ (iv) सिगरेट/सिगार तथा तम्बाकू पत्रक

परिशिष्ट "इ"

[अनुसूची I का पैरा 4(2) देखें]

जीडीआर/एडीआर निर्माण की व्यवस्था करने वाली भारतीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निगरानी

अनुदेश :

फार्म भरकर भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए।

1. कंपनी का नाम :
2. पंजीकृत कार्यालय का पता :
3. पत्र व्यवहार का पता :
4. विद्यमान कारोबार (कंपनी प्रमुखतः जिस गतिविधि में सन्तुष्ट है उसका एनआईसी कूट) :
5. प्रयोजन के लिए ब्यौरे जिसके लिए एडीआर/जीडीआर की वृद्धि हुई है। यदि विधियां विदेशी निवेश के लिए अभिनियोजित की थी तो उसके ब्यौरे :
6. विदेशी जमाकर्ता का नाम और पता :
7. निवेश का प्रमुख/प्रबंधक/मर्चेन्ट बैंकर का नाम और पता :
8. निर्माण के उप-प्रबंधक का नाम और पता :
9. भारतीय कस्टोडियन का नाम और पता :
10. एफआईपीबी अनुमोदन के ब्यौरे (कृपया संबंधित एन आई सी कूट को उद्धृत करें यदि जीडीआर स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत जारी किये गये हों) :
11. क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र सीमा (सैक्टरल कैप) लागू है, यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दें :

12. इक्विटी पूंजी के ब्यौरे

निर्गम से पूर्व

निर्गम के बाद

(क) प्राधिकृत पूंजी

(ख) निर्गमित और प्रदत्त पूंजी

(i) भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा धारित

(ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी कंपनियों/निष्कायों के अलावा विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक और उनके प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों की संख्या वाले विदेशी निवेशकों की सूची प्रस्तुत की जाए)

(iii) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्ति :

(iv) विदेशी संसाधन निवेशक द्वारा धारित :

(ग) कुल प्रदत्त पूंजी का अनिवासियों द्वारा धारित इक्विटी का प्रतिशत :

13. क्या निर्गम निजी नियोजन आधार पर था ? यदि हाँ, तो निवेशकों के और उनमें से प्रत्येक को जारी किए गए एडीआर/जीडीआर के ब्यौरे दें। :

14. जारी किये गये जीडीआर/एडीआर की संख्या :

15. आधारभूत शेयर के एडीआर/जीडीआर का प्रतिशत। :

परिशिष्ट 'ई'

[अनुसूची I का पैरा 4(3) देखें]

तिमाही विवरणी

(भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए)

1. कंपनी का नाम :

2. पता :

3. एडीआर/जीडीआर निर्गम तारीख :

4. जारी किये गये एडीआर/जीडीआर की कुल संख्या :

5. वर्धित की गयी, कुल राशि :

6. तिमाही की समाप्ति तक अर्जित ब्याज :

7. जारी करने का व्यय और कमीशन आदि :

8. प्रत्यावर्तित राशि :

9. विदेश में रखा हुआ बकाया :

ब्योरा

(i) बैंक जमा राशियाँ

(ii) खजाना बिल

(iii) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

10. अभी तक बकाया जीडीआर की संख्या :

11. तिमाही समाप्ति पर कंपनी के शेयर का मूल्य :

12. तिमाही समाप्ति पर विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में दर्शाए गए जीडीआर का मूल्य :

यह प्रमाणित किया जाता है कि एडीआर/जीडीआर से अर्जित निधि का निवेश शेयर बाजार अथवा सर्विस में नहीं किया गया है।

हस्ता०/-

हस्ता०/-

सनदी लेखाकार

कंपनी का प्राधिकृत हस्ताक्षर

“फार्म एफसी-जीपीआर”

[भारतीय रिजर्व बैंक के जिस क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में घोषणा करने वाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है उसके पास प्रस्तुत किया जाए।]

हम (कंपनी का नाम) -----

घोषित करते हैं कि दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी में प्रदत्त अनुमोदन के अधीन अनिवारियों को शेयर जारी करने के पात्र होने पर हम जारी किए गए शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करते हैं।

1. अनिवारियों को शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी का नाम और पता (पंजीकृत कार्यालय)
2. कंपनी पहले से मौजूद कंपनी है या हाल ही में गठित नई कंपनी है
3. कंपनी के कार्यकलाप

एनआईसी कोड**विवरण**

यदि एनआईसी कोड उस कार्यकलाप को नहीं दिया गया है तो कंपनी नजदीकी विस्तृत श्रेणी में वर्गीकृत हो। अगर कार्यकलाप को एनआईसी कोड में वर्गीकृत करना मुमकिन न हो तो सिर्फ ब्यौरा दिया जाए।

4. निर्गम किए गए शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर के ब्यौरे
 - (क) विदेशी निवेशक का नाम और देश
 - (ख) निवेशक की श्रेणी (विदेशी/विदेश में निवासी भारतीय/विदेशी कंपनी/निकाय/एफआईआई/विदेशी कंपनी/एफवीसीएफ, एफवीसीसी इत्यादि)
 - (ग) क्या शेयरों का स्वचालित मार्ग/सरकारी अनुमोदन अथवा अधिमानित/बोनस आधार पर से निर्गम किया गया है (जहां लागू हो, कृपया एसआईए/एफआईपीबी अनुमोदन क्रमांक दर्शाएं)
 - (घ) निर्गमित शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर के ब्यौरे (कृपया इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्यौरे अलग से दर्शाएं)

शेयरों/परिवर्तनीय
डिबेंचरों की संख्या
निर्गम मूल्य

शेयरों का अंकित मूल्य/
सम मूल्य (र.)/प्रिमियम रु.
प्रति शेयर, निर्धारित प्रिमियम
गेर कैपिटेशन शुल्क, आदि

कुल अंकित मूल्य
बोनस शेयर के
कालों में अनुपात

अनिवारियों को शेयर जारी करने के
कारण कुल अंतर्वाह (प्रिमियम सहित,
यदि कोई हो)

- (घ)(i) हम सूचीबद्ध कंपनी हैं, सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य और केन्द्र र. है।

अथवा

- (ii) कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, पूर्ववर्ती सीसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य और केन्द्र र. है।

अथवा

- (iii) अधिकार आधार पर शेयर जारी किए जा रहे हैं।

अथवा

- (iv) शेयर विलयन/डीमर्जर/समामेलन के फलस्वरूप जारी किए गए हैं।

5. कंपनी का पूंजी ढांचा

(मद 4 के अनुसार शेयर जारी करने के बाद)

इक्विटी

(रुपये)

अधिमानी

I. प्रदत्त पूंजी

II. (क) अनिवासी निवेश	ईक्यूटी	(रुपये) अधिमानी
(i) अनिवासी भारतीय/ विदेशी कंपनी निकाय		
(ii) अन्य (स्पष्ट करें)		
(ख) निवासी निवेश		
	कुल	
III. प्रदत्त पूंजी में अनिवासी निवेश का वर्तमान प्रतिशत [II क I के प्रतिशत के रूप में]	अनिवासी भारतीय/ विदेशी कंपनी निकाय अन्य कुल	-----% -----% -----%

घोषणा

हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि:—

- हमने 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. 20/2000-आरबी में दर्शाए गए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत शेयर जारी करने वाली प्रणाली का सावधानी से अनुपालन किया है।
- विदेशी/ईक्यूटी/ईक्यूटिवी (व्यक्तियों के अलावा) जिन्हें हमने शेयर जारी किए हैं उनका भारत में कोई भी पूर्व संयुक्त उद्यम या तकनीकी सहभागिता या ट्रेड मार्क करार है/नहीं है।
- हमें औद्योगिक अधिनियम 1951 (विकास और विनियम) या सरकार द्वारा अधिसूचित 1991 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- हम एसएसआई इकाई हैं और 24 प्रतिशत की निवेश सीमा का पालन किया गया है अथवा हम एसएसआई इकाई नहीं हैं (जो लागू न हो उसे हस्ताक्षर करके निकाल दें)।
- हमारा प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आने वाले सेक्टर नीति/अनुमत सीमा के भीतर है।

अथवा

- II. शेयर, दिनांक के-----एसआईए/एफआईपीबी अनुमोदन क्र.-----के अनुसार जारी किए गए हैं।

अथवा

- III. शेयर को अधिमानी आधार पर जारी किया गया है और अनिवासी को जारी शेयर का मूल्य, जिस मूल्य पर निवासी को शेयर जारी किए गए हैं, उससे कम नहीं है।

अथवा

- IV. जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।

अथवा

- V. ये अथवा अधिक भारतीय कंपनियां विलयन और समामेलन योजना के अंतर्गत जारी किए गए शेयर अथवा डिमर्जर अथवा भारतीय कंपनी द्वारा पुनः निर्मित, भारत में व्यापार द्वारा कयावत् अनुमोदित।

कृते----- (कंपनी का नाम/मुहर)

हस्ताक्षर

नाम (-----)

*पदनाम (-----)

तारीख :

स्थान :

*(कंपनी के वरिष्ठ/जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)।

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th June, 2003

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)
(Second Amendment) Regulations, 2003**

G.S.R. 558(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely :—

Short Title and Commencement :—

1. (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of the Regulations :—

2. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000.

A. In Regulation 2,

(i) after item (vii), the following item shall be inserted, namely :—

(vii) (a) 'Non-resident Indian (NRI) shall have the meaning assigned to it in clause (iv) of Regulation 2 of the Foreign Exchange Management (Investment in Firm or Proprietary Concern in India) Regulations, 2000.'

(ii) in item (viii), the words 'Non-resident Indian (NRI)' shall be deleted;

B. After Regulation 6, the following Regulations shall be inserted, namely :—

" 6A. Acquisition of Bonus shares :—

An Indian company may issue bonus shares to its non-resident shareholders, subject to the following conditions :

- (a) the shares against which bonus shares are issued by the company (hereinafter referred to as 'the original shares') were acquired or held by the non-resident shareholder in accordance with the Rules/ Regulations applicable to such acquisition;
- (b) the bonus shares acquired by the non-resident shareholder shall be subject to the same conditions including restrictions in regard to repatriability as are applicable to the original shares.

6 B. Report to RBI :—

A company issuing right shares or bonus shares in terms of Regulation 6 or Regulation 6A as the case may be, shall, within thirty days from the date of issue, report the transaction in Form FC-GPR to the Regional Office of the Reserve Bank of India under whose jurisdiction the Registered Office of the company is situated."

C. In Regulation 9, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) (i) A person resident outside India, not being a non-resident Indian or an overseas corporate body, may transfer by way of sale or gift the shares or convertible debentures held by him or it to any person resident outside India;

(ii) A non-resident Indian or an overseas corporate body may transfer by way of sale or gift, the shares or convertible debentures held by him or it to another non-resident Indian or overseas corporate body only;

Provided that the person to whom the shares are being transferred, in terms of clause (i) and (ii), has obtained prior permission of Central Government to acquire the shares if he has previous venture or tie up in India through investment in shares or debentures or a technical collaboration or a trade mark agreement or investment by whatever name called in the same field or allied field in which the Indian company whose shares are being transferred is engaged.

Provided further that the restriction in clauses (i) and (ii) shall not apply to the transfer of shares to International financial institutions such as Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Commonwealth Development Corporation (CDC), Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) and transfer of shares of an Indian company engaged in Information Technology sector.

(iii) A person resident outside India holding the shares or convertible debentures of an Indian company in accordance with these Regulations,

(a) may transfer the same to a person resident in India by way of gift;

(b) may sell the same on a recognized Stock Exchange in India through a registered broker."

D. In Schedule 1

- (a) in paragraph 5, in clause (a), after the words "SEBI guidelines", the words "as applicable" shall be inserted;
- (b) after paragraph 5, the following new paragraph shall be inserted, namely:

"5A. Issue price of ADRs/GDRs

Price of ADRs/GDRs to be issued to a person resident outside India may be decided by the Indian company—

- (a) where the issue is on public offer basis, in consultation with the Lead Manager to the issue; and
- (b) in other cases, as provided in paragraph 5 above."
- (c) In paragraph 6, in clause (a), after sub-clause (ii), the following shall be added, namely :
 "(iii) to obligations arising out of dividends declared/remitted after 14th July 2000 i.e. the date on which conditions of dividend balancing was withdrawn"
- (d) In paragraph 6, the existing sub-clause (b) shall be deleted

E Annexure A may be substituted with amended Annexure "A"

F Annexure B may be substituted with amended Annexure "B"

G Annexure C may be substituted with amended Annexure "C"

H Annexure D may be substituted with amended Annexure "D"

I The existing Form FC-GPR shall be substituted with the amended Form FC-GPR.

J In Schedule 2.

In Paragraph (1), for sub-paragraph (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) A registered FII is permitted to purchase shares/convertible debentures of an Indian company through offer/private placement, subject to the ceiling specified in sub-paragraph (4) of this paragraph and the Indian company is permitted to issue such shares;

Provided that —

- (i) in case of Public Offer, the price of the shares to be issued is not less than the price at which shares are issued to residents, and
- (ii) in case of issue by private placement, the price is not less than the price arrived in terms of SEBI guidelines or guidelines issued by erstwhile Controller of Capital Issues, as applicable."

K In Schedule 3,

- (i) in Paragraph 1, for sub-paragraph (i), the following shall be substituted, namely :—

"(i) NRIs may purchase and sell shares/convertible debentures under the Portfolio Investment Scheme through a branch designated by an Authorised Dealer for the purpose and duly approved by the Reserve Bank of India."

- (ii) For Paragraph 3, the following shall be substituted, namely :—

"3. Remittance/credit of sale/maturity proceeds of shares and/or debentures.

The net sale/maturity proceeds (after payment of taxes) of shares and/or debentures of an Indian company purchased by NRI or OCB under this scheme, may be allowed by the designated branch of an authorised dealer referred to in paragraph 1,

- (a) to be credited to NRO account of the NRI/OCB investor where the payment for purchase of shares and/or debentures sold was made out of funds held in NRO account or where the shares and/or debentures were purchased on non-repatriation basis, or
- (b) at the NRI or OCB investor's option, to be remitted abroad or credited to his/its NRE/FCNR/NRO account of the NRI, where shares and/or debentures were purchased on repatriation basis."

L In Schedule 4, after paragraph 2, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that the person to whom the shares are being transferred, has obtained prior permission of Central Government to acquire the shares if he has previous venture or tie up in India through investment in shares or debentures or a technical collaboration or a trade mark agreement or investment by whatever name called in the same field or allied field in which the Indian company whose shares are being transferred is engaged.”

Provided further that this restriction shall not apply to the transfer of shares to International Financial Institutions such as Asian Development Bank(ADB), International Finance Corporation(IFC), Commonwealth Development Corporation (CDC), Deutsche Entwicklungs Gesellschaft(DEG) and transfer of shares of an Indian company engaged in Information Technology sector.

[No. FEMA-94/2003-RB]

USHA THORAT, Executive Director

ANNEXURE A
(See paragraph 2)

(A) List of Activities for which Automatic Route of RBI for investment from person resident outside India is not available

1. Domestic Airlines
2. Petroleum Sector (except for private sector oil refining)
3. Investing companies in Infrastructure and Services Sector
4. Defence and Strategic Industries
5. Atomic Minerals
6. Print Media
7. Broadcasting
8. Postal Services
9. Courier Services
10. Establishment and Operation of satellite
11. Development of Integrated Township
12. Tea Sector

(B) List of activities or items for which FDI is prohibited.

1. Retail Trading
2. Atomic Energy
3. Lottery Business
4. Gambling and Betting
5. Housing and Real Estate business
6. Agriculture (excluding Floriculture, Horticulture, Development of Seeds, Animal Husbandry, Pisciculture and Cultivation of Vegetables, Mushrooms etc. under controlled conditions and services related to agro and allied sectors) and Plantations (Other than Tea plantations)

ANNEXURE B

(See paragraph 2)

Sectoral cap on investments by persons resident outside India

Sector	Investment Cap	Description of Activity/Items/Conditions
1	2	3
1. Private Sector Banking	49%	Subject to guidelines issued by RBI from time to time
2. Non-Banking Financial Companies	100%	FDI/NRI/OCB investments allowed in the following 19 NBFC activities shall be as per the levels indicated below : (a) Activities covered : 1. Merchant Banking 2. Under Writing 3. Portfolio Management Services 4. Investment Advisory Services 5. Financial Consultancy 6. Stock-broking 7. Asset Management 8. Venture Capital 9. Custodial Services 10. Factoring 11. Credit Reference Agencies 12. Credit Rating Agencies 13. Leasing & Finance 14. Housing Finance 15. Forex-broking 16. Credit Card Business 17. Money-changing Business 18. Micro-credit 19. Rural credit (b) Minimum Capitalisation norms for fund based NBFCs (i) for FDI upto 51%, US \$ 0.5 million to be brought in upfront (ii) If the FDI is above 51 % and upto 75 %, US \$ 5 million to be brought upfront (iii) If the FDI is above 75 % and upto 100 %, US \$ 50 million out of which \$ 7.5 million to be brought in upfront and the balance in 24 months (c) Minimum Capitalisation norms for non-fund based activities. Minimum Capitalisation norm of US \$ 0.5 million is applicable in respect of non-fund based NBFCs with foreign investment. (d) Foreign investors can set up 100% operating subsidiaries without the condition to disinvest a minimum of 25% of its equity to Indian entities, subject to bringing in US \$ 50 million as at (b) (iii) above (without any restriction on number of operating subsidiaries without bringing in additional capital) (e) Joint Venture operating NBFCs that have 75% or less than 75% foreign investment will also be allowed to set up subsidiaries for undertaking other NBFC activities, subject to the subsidiaries also complying with the applicable minimum capital inflow i.e. (b)(i) and (b)(ii) above.

1	2	3
		(f) FDI in the NBFC sector is put on automatic route subject to compliance with guidelines of the Reserve Bank of India. RBI would issue appropriate guidelines in this regard.
3. Insurance	26%	FDI upto 26% in the Insurance sector is allowed on the automatic route subject to obtaining licence from Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
4. Telecommunications	49%	<p>(i) In basic, Cellular, Value Added Services, and Global Mobile Personal Communications by Satellite, FDI is limited to 49% subject to licencing and security requirements and adherence by the companies (who are investing and the companies in which the investment is being made) to the license conditions for foreign equity cap and lock-in period for transfer and addition of equity and other license provisions.</p> <p>(ii) ISPs with gateways, radio paging and end-to-end bandwidth, FDI is permitted upto 74% with FDI, beyond 49% requiring Government approval. These services would be subject to licensing and security requirements.</p> <p>(iii) No equity cap is applicable to manufacturing activities.</p> <p>(iv) FDI upto 100% is allowed for the following activities in the telecom sector :</p> <p>(a) ISPs not providing gateways (both for satellite and submarine cables)</p> <p>(b) Infrastructure Providers providing dark fibre (IP Category I)</p> <p>(c) Electronic Mail, and</p> <p>(d) Voice Mail</p> <p>The above would be subject to the following conditions;</p> <p>(a) FDI upto 100% is allowed subject to the condition that such-companies would divest 26% of their equity in favour of Indian public in 5 years, if these companies are listed in other parts of the world.</p> <p>(b) The above services would be subject to licencing and security requirements, wherever required.</p> <p>(c) Proposal for FDI beyond 49% shall be considered by FIPB on case to case basis.</p>
5. Petroleum Refining (Private Sector)	100%	FDI permitted upto 100% in case of private Indian companies.
6. Housing and Real Estate	100%	<p>Only NRIs/OCBs are allowed to invest upto 100% in the areas listed below:</p> <p>(a) Development of serviced plots and construction of built-up residential premises</p> <p>(b) Investment in real estate covering construction of residential and commercial premises including business centers and offices</p> <p>(c) Development of townships</p> <p>(d) City and regional level urban infrastructure facilities, including both roads and bridges;</p> <p>(e) Investment in manufacture of building materials;</p> <p>(f) Investment in participatory ventures in (a) to (c) above.</p> <p>(g) Investment in Housing finance institutions which is also opened to FDI as an NBFC;</p>

1	2	3
7. Coal & Lignite		<p>(i) Private Indian companies setting up or operating power projects as well as coal and lignite mines for captive consumption are allowed FDI upto 100%.</p> <p>(ii) 100% FDI is allowed for setting up coal processing plants subject to the condition that the company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for washing or sizing.</p> <p>(iii) FDI upto 74% is allowed for exploration or mining of coal or lignite for captive consumption.</p> <p>(iv) In all the above cases, FDI is allowed upto 50% under the automatic route subject to the condition that such investment shall not exceed 49% of the equity of a PSU.</p>
8. Venture Capital Fund (VCF) and Venture Capital Company (VCC)		<p>Offshore Venture Capital Funds/companies are allowed to invest in domestic venture capital undertaking as well as other companies through the automatic route, subject only to SEBI regulation and sector specific caps on FDI.</p>
9. Trading		<p>Trading is permitted under automatic route with FDI upto 51% provided it is primarily export activities, and the undertaking is an export house/trading house super trading House star trading house. However, under the FIPB route:</p> <p>(i) 100% FDI is permitted in case of trading companies for the following activities.</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) exports; (b) bulk imports with export/expanded warehouse sales; (c) cash and carry wholesale trading; (d) other import of goods or services provided at least 75% is for procurement and sale of the same group and not for third party use or onward transfer/distribution/sales. <p>(ii) The following kinds of trading are also permitted, subject to provisions of Exim Policy.</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Companies for providing after sales services (that is not trading per se); (b) Domestic trading of products of JVs is permitted at the wholesale level for such trading companies who wish to market manufactured products on behalf of their Joint ventures in which they have equity participation in India; (c) Trading of hi-tech items/items requiring specialised after sales service; (d) Trading of items for social sector; (e) Trading of hi-tech, medical and diagnostic items; (f) Trading of items sourced from the small scale sector under which, based on technology provided and laid down quality specifications, a company can market that item under its brand name; (g) Domestic sourcing of products for exports; (h) Test marketing of such items for which a company has approval for manufacture provided such test marketing facility will be for a period of two years, and investment in setting up manufacturing facilities commence simultaneously with test marketing.;

1	2	3
		(i) FDI upto 100% permitted for e-commerce activities subject to the condition that such companies would divest 26% of their equity in favour of the Indian public in five years, if these companies are listed in other parts of the world. Such companies would engage only in business to business (B2B) e-commerce and not in retail trading.
10. Power	100%	FDI allowed upto 100% in respect of projects relating to electricity generation, transmission and distribution, other than atomic reactor power plants. There is no limit on the project cost and quantum of foreign direct investment.
11. Drugs & Pharmaceuticals	100%	FDI permitted upto 100% for manufacture of drugs and pharmaceuticals provided the activity does not attract compulsory licensing or involve use of recombinant DNA technology and specific cell/tissue targeted formulations. FDI proposal for the manufacture of licensable drugs and pharmaceuticals and bulk drugs produced by recombinant DNA technology and specific cell/tissue targeted formulations will require prior Govt. approval.
12. Road and highways, Ports and harbors	100%	In projects for construction and maintenance of roads, highways, vehicular bridges, toll roads, vehicular tunnels, ports and harbours.
13. Hotel & Tourism	100%	The term hotels include restaurants, beach resorts and other tourist complexes providing accommodation and/or catering and food facilities to tourists. Tourism related industry include travel agencies, tour operating agencies and tourist transport operating agencies, units providing facilities for cultural, adventure and wild life experience to tourists, surface, air and water transport facilities to tourists, leisure, entertainment, amusement, sports and health units for tourists and Convention/Seminar units and organisations. For foreign technology agreements, automatic approval is granted if (i) Upto 3% of the capital cost of the project is proposed to be paid for technical and consultancy services including fees for architects, design, supervision, etc. (ii) Upto 3% of the net turnover is payable for franchising and marketing/publicity support fee, and Upto 10% of gross operating profit is payable for management fee, including incentive fee.
14. Mining	74%	(i) For exploration and mining of diamonds and precious stones FDI is allowed upto 74% under automatic route,
	100%	(ii) For exploration and mining of gold and silver and minerals other than diamonds and precious stones, metallurgy and processing FDI is allowed upto 100% under automatic route, (iii) Press Note 18 (1998 series) dated 14-12-98 would not be applicable for setting up 100% owned subsidiaries in so far as the mining sector is concerned, subject to a declaration from the applicant that he has no existing joint venture for the same area and/or the particular mineral.
15. Advertising	100%	Advertising Sector FDI upto 100% allowed on the automatic route
16. Films	100%	Film Sector (Film production, exhibition and distribution including related services/products)

1	2	3
		FDI upto 100% allowed on the automatic route with no entry-level condition
17. Airports	74%	Govt approval required beyond 74%
18. Mass Rapid Transport Systems	100%	FDI upto 100% is permitted on the automatic route in mass rapid transport system in all metros including associated real estate development.
19. Pollution Control & Management	100%	In both manufacture of pollution control equipment and consultancy for integration of pollution control systems is permitted on the automatic route.
20. Special Economic Zones	100%	All manufacturing activities except: <ul style="list-style-type: none"> (i) Arms and ammunition, Explosives and allied items of defence equipments, Defence aircrafts and warships, (ii) Atomic substances, Narcotics and Psychotropic Substances and hazardous Chemicals, (iii) Distillation and brewing of Alcoholic drinks, and (iv) Cigarette/cigars and manufactured tobacco substitutes.

Annexure 'C'

[Refer to paragraph 4(2) of Schedule I]

Return to be filed by an Indian company who has arranged issue of GDR/ADR**Instructions :**

The form should be completed and submitted to the Reserve Bank of India, Foreign Investment Division, Central Office, Mumbai.

1. Name of the Company :
2. Address of Registered Office :
3. Address for correspondence :
4. Existing Business (Please give the NIC Code of the activity in which the company is predominantly engaged) :
5. Details of the purposes for which GDRs/ADRs have been raised. :
If funds are deployed for overseas investment, details thereof.
6. Name and address of the Depository abroad :
7. Name and Address of the Lead/Manager Investment/ Merchant Banker :
8. Name and addresses of the Sub-Managers to the issue :
9. Name and address of the Indian custodians :
10. Details of FIPB approval :
(Please quote the relevant NIC Code if the GDRs are being issued under the Automatic Route)
11. Whether any overall sectoral cap for foreign investment is applicable. If yes, please give details. :
12. Details of the Equity Capital :

	Before Issue	After Issue
(a) Authorised Capital		
(b) Issued and Paid-up Capital		
(i) Held by persons Resident in India		

(ii) Held by foreign investors other than Flls/NRIs/PIOs/OCBs (A list of foreign investors holding more than 10 per cent of the paid-up capital and number of shares held by each of them should be furnished)

(iii) Held by NRIs/PIOs/OCBs

(iv) Held by Flls.

Total Equity held by non-residents

(c) Percentage of equity held by non-residents to total paid-up capital

13. Whether issue was on private placement basis. If yes, please give details of the investors and ADRs/GDRs issued to each of them :

14. Number of GDRs/ADRs issued :

15. Ratio of GDRs/ADRs to underlying shares :

16. Issue Related Expenses :

(a) Fee paid/payable to Merchant Bankers/Lead Manager

(i) Amount (in US \$ etc.)

(ii) Amount as percentage to the total issue

(b) Other Expenses

17. Whether funds are kept abroad. If yes, name and address of the bank :

18. Details of the listing arrangement :
Name of Stock Exchange
Date of commencement of trading :

19. The date on which ADRs/GDRs issue was launched :

20. Amount raised (in US \$) :

21. Amount repatriated (in US \$) :

Certified that all the conditions laid down by Government of India and Reserve Bank of India have been complied with.

Sd/-

Chartered Accountant

Sd/-

Authorised Signatory of the Company

Annexure 'D'

[Refer to paragraph 4(3) of Schedule I]

Quarterly Return

(to be submitted to the Reserve Bank of India, Foreign Investment Division, Central Office, Mumbai)

1. Name of Company :
2. Address :
3. GDR/ADR issue launched on :
4. Total No. GDRs/ADRs issued :
5. Total amount raised :
6. Total interest earned till end of quarter :
7. Issue Expenses and commissions etc. :
8. Amount repatriated :
9. Balance kept abroad Details :
- (i) Banks Deposits
- (ii) Treasury Bills
- (iii) Others (Please specify)

10. No. of GDRs still outstanding :
11. Company's share price at the end of the quarter :
12. GDR price quoted on overseas stock exchange :
as at the end of the quarter

Certified that funds raised through ADRs/GDRs have not been invested in stock market or real estate.

Sd/-
Chartered Accountant

Sd/-
Authorised Signatory of the Company

"FORM FC-GPR"

(To be filed with the Regional Office of the RBI under whose jurisdiction the registered office of the company making the declaration is situated)

We (Name of the Company) _____

Declare that, being eligible to issue shares to non-residents under the permission granted under Notification No.FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000, furnish the following information in connection with shares issued.

1. Name and address (Registered office)
of the Indian company issuing shares
to non-residents
2. Whether existing company or new
company recently formed
3. Activities of the company

NIC Code

Description

(In case no NIC code has been allotted to the activity, the company may classify in the nearest broad category. In case it is not at all possible to classify the activity under the NIC Code, only description may be given).

4. Particulars of shares/convertible debentures issued

- (a) Name and country of the foreign investor
- (b) Category of investor (Foreign National/NRI/OCB/FII/Foreign Company, Foreign Venture Capital Fund, Foreign Venture Capital Company etc.)
- (c) Whether the shares are issued under Automatic Route/Government Approval or on rights/bonus basis (Please quote SIA/FIPB approval number where applicable)
- (d) Details of shares/convertible debentures issued (Please furnish details for equity shares, preference shares and convertible debentures separately)

No. of shares/ convertible debentures Issue Price	Face value of shares At par (Rs.)/premium of Rs. - per share, control premium non-competition fee etc.	Total face value Ratio in case of bonus shares
---	--	--

Total inflow on account of
issue of shares to non-residents
(including premium if any)

}
}
}

Rs.

- (d) (i) We are a listed company, price in terms of SEBI guidelines per share is Rs.

OR

- (ii) The company is not listed, fair value of the share in terms of guidelines issued by the erstwhile CCI is Rs.

OR

- (iii) Shares are issued on rights basis

OR

- (iv) Shares have been issued as a result of merger/de-merger/amalgamation

5. Capital structure of the company (after issue of shares as per item 4)

	Equity	(Rupees) Preference
I Paid up capital		
II (a) Non-resident Investment		
(i) NRI/OCB		
(ii) Others (specify)		
(b) Resident investment		
	Total	
III Existing percentage of	} NRIs/OCBs	_____ %
non-resident investment	} Others	_____ %
in the paid up capital	}	
[If a as a percentage of I]	Total	_____ %

Declaration

We hereby declare that :

1. We have carefully followed the procedure for issue of shares as laid down under the Automatic Route as indicated in the Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000.
2. Foreign equity (ies) (other than individuals) to whom we have issued shares does/do not have any previous joint venture or technical collaboration or trade mark agreement in India in the same or allied field.
3. We don't require an Industrial Licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or in terms of locational policy notified by the Government under the new Industrial Policy of 1991.
4. We are an SSI unit & the investment limit of 24 % has been observed, OR we are not an SSI unit.

(Delete whichever is not applicable under signature)

5. Our proposal is within the sectoral policy/cap permissible under the automatic route of RBI.

OR

- II Shares have been issued in terms of SIA/FIPB approval No. _____ dated _____

OR

- III Shares have been issued on rights basis and the shares are issued to non-residents at a price that is not lower than that at which shares issued to residents.

OR

- IV Shares issued are bonus shares.

OR

- V Shares have been issued under a scheme of merger and amalgamation of two or more Indian companies or reconstruction by way of demerger or otherwise of an Indian company, duly approved by a court in India.

For _____ (Name of the Company/ Seal)

Signature

Name : (_____)

*Designation : _____

Date:

Place:

(* To be signed by senior official/ responsible person in the company)